



# Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC  
| SSC | BANK RAILWAY Exam

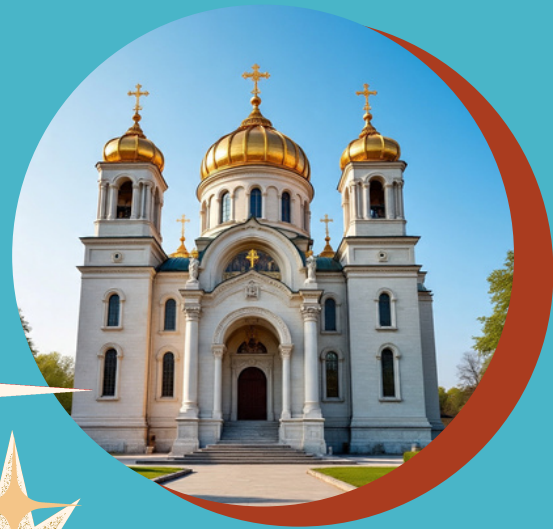


## BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

1 - 7 FEB 2026

1ST WEEK OF FEBRUARY

50+ MCQ  
with detailed  
explanation



- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



**Ques: Why has the Reserve Bank of India (RBI) proposed changes to the framework for calculating banks' net foreign exchange (FX) exposure and capital requirements?**

**भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के शुद्ध विदेशी मुद्रा (FX) जोखिम और पूंजी आवश्यकता की गणना के ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव क्यों दिया है?**

- A) To align India's FX risk norms with global standards and ensure uniformity / भारत के एफएक्स जोखिम मानदंडों को वैश्विक मानकों के अनुरूप और एकरूप बनाने के लिए
- B) To promote higher foreign currency lending / विदेशी मुद्रा ऋण को बढ़ावा देने के लिए
- C) To reduce banks' capital burden on FX exposure / एफएक्स जोखिम पर बैंकों का पूंजी बोझ कम करने के लिए
- D) To exempt small banks from FX risk regulations / छोटे बैंकों को एफएक्स जोखिम नियमों से छूट देने के लिए
- E) To postpone implementation of FX risk norms indefinitely / एफएक्स जोखिम नियमों के क्रियान्वयन को अनिश्चितकाल तक टालने के लिए

**Answer: Option A**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The RBI has proposed changes to the framework for calculating banks' net foreign exchange (FX) exposure and the associated capital requirements.
- आरबीआई ने बैंकों के शुद्ध विदेशी मुद्रा (FX) जोखिम और उससे जुड़ी पूंजी आवश्यकताओं की गणना के ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।
- The objective is to align India's FX risk norms with global standards prescribed by the Basel Committee and ensure uniform implementation across all regulated entities.
- इसका उद्देश्य बेसल समिति द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत के एफएक्स जोखिम मानदंडों को बनाना और सभी विनियमित संस्थाओं में एकरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
- Under the proposed framework, banks will be required to maintain a minimum capital charge of 9% on their net open foreign exchange positions.
- प्रस्तावित ढांचे के तहत, बैंकों को अपने शुद्ध खुले विदेशी मुद्रा जोखिम पर न्यूनतम 9% की पूंजी रखना अनिवार्य होगा।
- The RBI has invited public feedback on these proposals.
- आरबीआई ने इन प्रस्तावों पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। (फीडबैक)

- The proposed changes are expected to come into effect from 1 April 2027.
  - ये प्रस्तावित बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होने की संभावना है।
- 
- 

**Ques: What key insight was revealed by SEBI's survey on Indian households' participation in the securities market?**

**भारतीय घरों की प्रतिभूति बाज़ार में भागीदारी को लेकर सेबी (SEBI) के सर्वेक्षण से कौन सा प्रमुख तथ्य सामने आया?**

- A) More than 50% households actively invest in equities and bonds / आधे से अधिक घर इक्विटी और बॉन्ड में सक्रिय निवेश करते हैं
- B) Awareness and participation levels are almost equal / जागरूकता और भागीदारी का स्तर लगभग समान है
- C) Only about 9.5% of Indian households participate despite higher awareness / उच्च जागरूकता के बावजूद केवल लगभग 9.5% घर ही भागीदारी करते हैं
- D) Rural households have higher participation than urban households / ग्रामीण घरों की भागीदारी शहरी घरों से अधिक है
- E) Participation is highest in complex instruments like derivatives and AIFs / डेरिवेटिव्स और AIFs जैसे जटिल साधनों में भागीदारी सबसे अधिक है

**Answer: Option C**

---

---

**Explanation | व्याख्या:**

- A SEBI survey revealed that out of 33.72 crore Indian households, only 3.21 crore households (9.5%) invest in securities such as equities, mutual funds, and corporate bonds.
- सेबी के सर्वेक्षण में पाया गया कि 33.72 करोड़ भारतीय घरों में से केवल 3.21 करोड़ घर (9.5%) ही इक्विटी, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे प्रतिभूति बाज़ार में निवेश करते हैं।
- Although 63% households (around 21.3 crore) are aware of at least one market-linked product, actual participation remains very low at 9.5%.
- लगभग 63% घर करीब 21.3 करोड़ संबंधित उत्पाद के बारे में कम से कम एक बाज़ार (जागरूक हैं, लेकिन वास्तविक भागीदारी केवल 9.5% ही है।
- The survey was conducted by Kantar between May and July 2025, covering over 90,000 households across 400 cities and 1,000 villages.

- यह सर्वेक्षण कांतर )Kantar) द्वारा मई से जुलाई 2025 के बीच किया गया, जिसमें 400 शहरों और 1,000 गांवों के 90,000 से अधिक घर शामिल थे।
- Nearly 30.51 crore households remain outside the securities market, highlighting significant under-penetration despite strong market growth over the past decade.
- लगभग 30.51 करोड़ घर अब भी प्रतिभूति बाज़ार से बाहर हैं, जो पिछले एक दशक में तेज़ बाज़ार वृद्धि के बावजूद कम पहुंच को दर्शाता है।
- Awareness is highest for mutual funds (53%) and ETFs (49%), while participation in complex instruments like corporate bonds, derivatives, REITs, InvITs, and AIFs is extremely limited.
- म्यूचुअल फंड (53%) और ETF (49%) के प्रति जागरूकता सबसे अधिक है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, REITs, InvITs और AIFs जैसे जटिल साधनों में भागीदारी बहुत सीमित है।
- Urban households show higher awareness (74%) compared to rural households (56%), reflecting clear geographic disparities.
- शहरी घरों में जागरूकता (74%) ग्रामीण घरों (56%) की तुलना में अधिक पाई गई, जो भौगोलिक असमानता को दर्शाती है।

---

**Ques: What is the key objective of the newly launched Aadhaar App dedicated to the nation?**

**राष्ट्र को समर्पित नए आधार ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है?**

- A) To replace physical Aadhaar cards completely / भौतिक आधार कार्ड को पूरी तरह से बदलना
- B) To provide a secure, convenient and privacy-first digital identity platform / सुरक्षित, सुविधाजनक और गोपनीयताप्रथम डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म प्रदान करना-
- C) To enable only biometric authentication for all services / सभी सेवाओं के लिए केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्षम करना
- D) To store Aadhaar numbers with service providers / सेवा प्रदाताओं के पास आधार नंबर संग्रहीत करना
- E) To limit Aadhaar usage to government services only / आधार के उपयोग को केवल सरकारी सेवाओं तक सीमित करना

**Answer: Option B**

---

## Explanation | व्याख्या:

- Minister of State for Commerce and Industry and Electronics & Information Technology, Shri Jitin Prasada, dedicated the new Aadhaar App to the nation.
- वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने नए आधार ऐप को राष्ट्र को समर्पित किया।
- The Aadhaar App has been developed by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) as a next-generation mobile application.
- आधार ऐप को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा एक नेक्स्ट जेनरेशन-मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में विकसित किया गया है।
- It provides Aadhaar Number Holders with a secure, convenient and privacy-first way to carry, share, show and verify their digital identity.
- यह आधार संख्या धारकों को अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित, सुविधाजनक और गोपनीयता आधारित तरीके से रखने-, साझा करने, दिखाने और सत्यापित करने की सुविधा देता है।
- The app supports multiple real-life use cases such as hotel check-ins via OVSE QR code scanning, optional face verification, age verification for cinema tickets, hospital admissions, and verification of gig workers.
- यह ऐप OVSE क्यूआर कोड के माध्यम से होटल चेकइन-, वैकल्पिक फेस वेरिफिकेशन, सिनेमा टिकट के लिए आयु सत्यापन, अस्पताल प्रवेश और गिग वर्कर्स के सत्यापन जैसे कई वास्तविक उपयोग मामलों को सपोर्ट करता है।
- Advanced features include face verification for proof of presence, one-click biometric lock/unlock, viewing authentication history, and a QR-based contact card.
- उन्नत सुविधाओं में उपस्थिति प्रमाण के लिए फेस वेरिफिकेशन, एक क्लिक बायोमेट्रिक-लॉकअनलॉक/, प्रमाणीकरण इतिहास देखना और क्यूआरआधारित कॉन्टैक्ट कार्ड शामिल हैं।
- The app allows management of up to five Aadhaar profiles on one device under the concept of “One Family – One App” and enables mobile number updates along with address updates.
- यह ऐप “वन फैमिली – वन ऐप” की अवधारणा के तहत एक डिवाइस पर पाँच तक आधार प्रोफाइल प्रबंधित करने की सुविधा देता है तथा पते के साथ साथ मोबाइल नंबर अपडेट करने की भी अनुमति देता है।
- It ensures data minimisation by sharing only digitally signed verifiable credentials and not storing Aadhaar numbers with verifiers, in line with the DPDP Act.
- यह सत्यापनकर्ताओं के पास आधार नंबर संग्रहीत न कर केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण साझा कर डेटा न्यूनतमकरण सुनिश्चित करता है, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम के अनुरूप है।

**Ques: Who has been appointed as the Managing Director & CEO of Fino Payments Bank for a tenure of three years till May 01, 2029?**

फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) के रूप में तीन वर्ष )01 मई 2029 तकके कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है (?)

- A) Rajesh Kumar / राजेश कुमार
- B) Deepak Mehta / दीपक मेहता
- C) Anil Sharma / अनिल शर्मा
- D) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा
- E) Rishi Gupta / ऋषि गुप्ता

**Answer: Option E**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- Mr. Rishi Gupta has been appointed as the Managing Director & CEO of Fino Payments Bank for a tenure of three years until May 01, 2029.
  - श्री ऋषि गुप्ता को फिनो पेमेंट्स बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीन वर्ष के लिए )01 मई 2029 तक (नियुक्त किया गया है।
  - Fino Payments Bank has received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) for conversion into a Small Finance Bank, becoming the first among payments banks to receive such approval.
  - फिनो पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है।
  - Fino Payments Bank was established in 2015 and its headquarters is located in Navi Mumbai.
  - फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है।
  - The tagline of Fino Payments Bank is “Qadar Aapki Mehnat Ki”.
  - फिनो पेमेंट्स बैंक की टैगलाइन “कदर आपकी मेहनत की” है।
- 

**Ques: Why did the Department of Posts (DoP) sign an agreement with Stock Holding Services Limited (SSL)?**

डाक विभाग (DoP) ने स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (SSL) के साथ समझौता क्यों किया?

- A) To introduce postal savings bonds / डाक बचत बांड शुरू करने के लिए

- B) To promote access to regulated capital market services for citizens / नागरिकों के लिए विनियमित पूंजी बाज़ार सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए
- C) To privatize selected post offices / चयनित डाकघरों का निजीकरण करने के लिए
- D) To replace banks with post offices for all investments / सभी निवेशों के लिए बैंकों को डाकघरों से बदलने के लिए
- E) To launch a new digital currency platform / नया डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए

**Answer: Option B**

---

### **Explanation | व्याख्या:**

- The Department of Posts (DoP), Ministry of Communications, Government of India, signed an agreement with Stock Holding Services Limited (SSL) to promote access to regulated capital market services for citizens across the country.
- भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (DoP) ने नागरिकों के लिए विनियमित पूंजी बाज़ार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (SSL) के साथ समझौता किया है।
- India Post, with its extensive nationwide network of over 1.65 lakh post offices, including a strong presence in rural and remote areas, plays a key role in extending financial services to underserved populations.
- 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के व्यापक राष्ट्रीय नेटवर्क और ग्रामीण व दूरदराज़ क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण इंडिया पोस्ट वंचित वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- Under the agreement, citizens will be able to access SSL's services through digital utilities such as onboarding links and QR codes available on official platforms and at selected post offices.
- इस समझौते के तहत नागरिक आधिकारिक प्लेटफॉर्म और चयनित डाकघरों पर उपलब्ध ऑनबोर्डिंग लिंक और क्यूआर कोड जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिए SSL की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- The services include opening demat and trading accounts, investing in mutual funds, participating in IPOs, and accessing other permitted investment products.
- इन सेवाओं में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश, आईपीओ में भागीदारी और अन्य अनुमत निवेश उत्पाद शामिल हैं।

**Ques: What is the maximum timeline prescribed by RBI for banks to take credit decisions on loans up to ₹25 lakh for Micro and Small Enterprises? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए ₹25 लाख तक के ऋण पर क्रेडिट निर्णय लेने हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित अधिकतम समय-सीमा क्या है?**

- A) 7 working days
- B) 10 working days
- C) 14 working days
- D) 21 working days
- E) 30 working days

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The investment and turnover limits for classification of MSMEs have been revised to enable higher efficiency of scale, technology upgradation, better access to capital, and global competitiveness.
- एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमाओं में संशोधन किया गया है ताकि बड़े पैमाने की दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी तक बेहतर पहुंच और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके।
- As per RBI (informed by DFS), for loans up to ₹25 lakh to Micro and Small Enterprises, banks must take credit decisions within 14 working days.
- डीएफएस द्वारा सूचित आरबीआई के अनुसार, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को ₹25 लाख तक के ऋण के लिए बैंकों को 14 कार्यदिवसों के भीतर क्रेडिट निर्णय लेना होगा।
- For loans above ₹25 lakh, timelines will follow board-approved sanction time norms of banks.
- ₹25 लाख से अधिक के ऋण के लिए समय-सीमा बैंकों के बोर्ड-अनुमोदित स्वीकृति मानकों के अनुसार होगी।
- Banks are required to prominently display MSME credit-related information, timelines, and indicative document checklists on their websites.
- बैंकों को एमएसएमई से जुड़े क्रेडिट विवरण, समय-सीमा और दस्तावेज़ सूची अपनी वेबसाइट पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
- Under CGTMSE, loan applications, sanctions, and disbursements under the Credit Guarantee Scheme (CGS) for MSEs are monitored quarterly by the Empowered Committee on MSME chaired by RBI along with SLBCs.

- सीजीटीएमएसई के तहत, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGS) में ऋण आवेदन, स्वीकृति और वितरण की तिमाही निगरानी आरबीआई अध्यक्षता वाली एमएसएमई सशक्त समिति और एसएलबीसी द्वारा की जाती है।
  - The credit guarantee cover for MSEs has been enhanced from ₹5 crore to ₹10 crore with effect from 01.04.2025 under CGS.
  - सीजीएस के तहत एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 01.04.2025 से ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।
- 
- 

**Ques: Which bank has received RBI approval to open a branch at the International Financial Services Centre (IFSC) in GIFT City, Gujarat?  
किस बैंक को गुजरात के GIFT सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में शाखा खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिली है?**

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Punjab & Sind Bank / पंजाब एंड सिंध बैंक

**Answer: Option E**

---

---

**Explanation | व्याख्या:**

- Punjab & Sind Bank has received approval from the Reserve Bank of India (RBI) to open a branch at the International Financial Services Centre (IFSC) in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat.
- पंजाब एंड सिंध बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT सिटी के IFSC में शाखा खोलने की अनुमति मिली है।
- GIFT City IFSC is India's premier international financial hub, created to facilitate cross-border financial transactions.
- GIFT सिटी IFSC भारत का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है, जिसे सीमा-पार वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है।
- It provides a world-class ecosystem for international trade finance, offshore banking, and capital market activities.
- यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त, ऑफशोर बैंकिंग और पूंजी बाज़ार गतिविधियों के लिए

विश्वस्तरीय ढांचा उपलब्ध कराता है।

### About Punjab & Sind Bank :

- Established : 1908
- HQ : New Delhi
- MD & CEO : Swarup Kumar Saha
- Tagline : Where service is a way of life

---

**Ques: As per the revised World Bank International Poverty Line, what was India's extreme poverty rate in 2022–23?**

**संशोधित विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार 2022–23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी?**

- A) 3.1%
- B) 4.5%
- C) 5.3%
- D) 12.9
- E) 23.9%

**Answer: Option C**

---

### Explanation | व्याख्या:

- The World Bank has revised the International Poverty Line (IPL) from USD 2.15 to USD 3.00 per day, adjusted for 2021 Purchasing Power Parity (PPP).
- विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) को USD 2.15 प्रति दिन से बढ़ाकर USD 3.00 प्रति दिन कर दिया है, जो 2021 की क्रय शक्ति समता (PPP) के अनुसार समायोजित है।
- The revision accounts for changes in global price levels and consumption patterns.
- यह संशोधन वैश्विक मूल्य स्तर और उपभोग पैटर्न में आए बदलावों को दर्शाता है।
- According to the revised IPL, India's extreme poverty rate in 2022–23 stood at 5.3%.
- संशोधित IPL के अनुसार, वर्ष 2022–23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर 5.3% रही।
- India's lower-middle-income poverty rate in 2022–23 was estimated at 23.9%.

- 2022–23 में भारत की निम्न-मध्यम आय वर्ग गरीबी दर 23.9% आंकी गई।
  - These estimates are highlighted in the Economic Survey.
  - ये अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए गए हैं।
- 
- 

**Ques: In which locations will the pilot project of CBDC-based “digital food currency” under the free ration scheme be rolled out?**

**मुफ्त राशन योजना के तहत CBDC आधारित “डिजिटल फूड करेंसी” की पायलट परियोजना किन स्थानों पर शुरू की जाएगी?**

- A) Chandigarh, Puducherry and three districts of Gujarat / चंडीगढ़, पुदुचेरी और गुजरात के तीन जिले
- B) Delhi, Mumbai and Chennai / दिल्ली, मुंबई और चेन्नई
- C) Gujarat and Rajasthan only / केवल गुजरात और राजस्थान
- D) All Union Territories of India / भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश
- E) Punjab, Haryana and Himachal Pradesh / पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश

**Answer: Option A**

---

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Government of India is set to roll out a pilot project for Central Bank Digital Currency (CBDC), also called “digital food currency”, under the free ration scheme.
- भारत सरकार मुफ्त राशन योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) यानी “डिजिटल फूड करेंसी” का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है।
- The pilot will be implemented in Chandigarh, Puducherry, and three districts of Gujarat.
- यह पायलट चंडीगढ़, पुदुचेरी और गुजरात के तीन जिलों में लागू किया जाएगा।
- Beneficiaries will receive monthly digital food coupons directly into an RBI-enabled digital wallet on their mobile phones.
- लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर RBI-सक्षम डिजिटल वॉलेट में मासिक डिजिटल फूड कूपन मिलेंगे।
- Coupons can be redeemed at ration shops by scanning the QR code of the shop owner to obtain free foodgrains.

- राशन दुकानदार के QR कोड को स्कैन कर कूपन भुनाए जा सकेंगे और निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त होगा।
- A soft launch was conducted earlier in Ahmedabad with 25 beneficiaries.
- इससे पहले अहमदाबाद में 25 लाभार्थियों के साथ इसका सॉफ्ट लॉन्च किया गया था।
- The next phase will cover Anand, Sabarmati and Dahod districts of Gujarat.
- अगले चरण में गुजरात के आणंद, साबरमती और दाहोद जिलों को शामिल किया जाएगा।

---

**Ques: Who has issued draft guidelines on resolution plans for borrowers affected by natural disasters?**

**प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाओं पर मसौदा दिशानिर्देश किसने जारी किए हैं?**

- A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- B) National Disaster Management Authority / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- C) State Governments / राज्य सरकारें
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक

**Answer: Option E**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued draft guidelines for banks and other regulated entities on resolution plans during natural disasters.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समाधान योजनाओं को लेकर बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- The framework will be applicable from April 1, and RBI has invited public and stakeholder feedback until February 17.
- यह ढांचा 1 अप्रैल से लागू होगा और RBI ने 17 फरवरी तक सार्वजनिक एवं हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
- The proposed framework requires banks to proactively plan for natural calamities while framing their credit policies, instead of relying on ad hoc relief measures.

- प्रस्तावित ढांचे के तहत बैंकों को तदर्थ राहत उपायों के बजाय क्रेडिट नीतियाँ बनाते समय प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम योजना बनानी होगी।
  - Banks will need to assess climate risks in advance and prepare pre-defined resolution mechanisms.
  - बैंकों को जलवायु जोखिमों का पूर्व मूल्यांकन कर पूर्व-निर्धारित समाधान तंत्र तैयार करना होगा।
  - RBI has clarified that only standard borrowers will be eligible for relief.
  - RBI ने स्पष्ट किया है कि केवल मानक (स्टैंडर्ड) उधारकर्ता ही राहत के पात्र होंगे।
  - Borrowers who have not defaulted for more than 30 days at the time of the disaster will qualify for relief.
  - आपदा के समय जिन उधारकर्ताओं ने 30 दिनों से अधिक की चूक नहीं की है, वे राहत के लिए पात्र होंगे।
- 
- 

**Ques: At the end of December 2025, India's fiscal deficit stood at what percentage of the FY26 Budget Estimate?**

**दिसंबर 2025 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा FY26 के बजट अनुमान का कितना प्रतिशत था?**

- A) 48.0%
- B) 50.2%
- C) 52.8%
- D) 54.5%
- E) 56.7%

**Answer: Option D**

---

---

**Explanation | व्याख्या:**

- At the end of December 2025, India's fiscal deficit stood at ₹8.55 lakh crore, which was 54.5% of the FY26 Budget Estimate.
- दिसंबर 2025 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा ₹8.55 लाख करोड़ रहा, जो FY26 के बजट अनुमान का 54.5% था।
- This level was lower than the 56.7% of the annual target recorded during the same period in the previous year.
- यह पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 56.7% के स्तर से कम था।
- The improvement in fiscal position was driven by stronger tax revenues and a

fiscal surplus recorded in December.

- राजकोषीय स्थिति में यह सुधार मजबूत कर राजस्व और दिसंबर में दर्ज राजकोषीय अधिशेष के कारण हुआ।
- Gross tax revenues rose sharply by 32.3% in December, taking overall growth during April–December to 8.5%.
- दिसंबर में सकल कर राजस्व 32.3% बढ़ा, जिससे अप्रैल–दिसंबर अवधि की कुल वृद्धि 8.5% हो गई।
- Capital expenditure growth slowed during this period, which helped in containing the fiscal deficit.
- इस अवधि में पूंजीगत व्यय की वृद्धि धीमी रही, जिससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिली।
- The government has targeted limiting the full-year FY26 fiscal deficit to 4.4% of GDP.
- सरकार ने पूरे FY26 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP के 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है।

---

**Ques: After the proposed merger of Union Bank of India and Bank of India, what will be the overall ranking of the combined entity in India?  
प्रस्तावित विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया की संयुक्त इकाई भारत में किस स्थान पर होगी?**

- A) Largest bank / सबसे बड़ा बैंक
- B) Second-largest bank / दूसरा सबसे बड़ा बैंक
- C) Third-largest bank / तीसरा सबसे बड़ा बैंक
- D) Fourth-largest bank / चौथा सबसे बड़ा बैंक
- E) Fifth-largest bank / पाँचवाँ सबसे बड़ा बैंक

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The initial merger process between Union Bank of India and Bank of India has begun and may be completed by the end of the calendar year.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के बीच विलय की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे कैलेंडर वर्ष के अंत तक पूरा किया जा सकता है।

- The Government of India aims to merge smaller public sector banks with larger ones to reduce the number of PSU banks from 12 to about 4–5.
- भारत सरकार छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़े बैंकों में विलय कर 12 के बजाय लगभग 4–5 बड़े PSU बैंक बनाना चाहती है।
- The merger would create one of India's largest public sector lenders with an expanded balance sheet, branch network, and customer base.
- यह विलय विस्तारित बैलेंस शीट, शाखा नेटवर्क और ग्राहक आधार के साथ भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में से एक का निर्माण करेगा।
- The combined entity is expected to become the second-largest PSU bank with assets of about ₹25.4 lakh crore in FY25.
- संयुक्त इकाई FY25 में लगभग ₹25.4 लाख करोड़ की परिसंपत्तियों के साथ दूसरा सबसे बड़ा PSU बैंक बन जाएगी।
- Overall, it would be the third-largest bank in India after State Bank of India (SBI) and HDFC Bank.
- कुल मिलाकर, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और HDFC बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।

**Ques: Which bank has launched India's first savings account linked to 100% of the RBI Repo rate?**

**किस बैंक ने भारत का पहला 100% RBI रेपो रेट से जुड़ा बचत खाता लॉन्च किया है?**

- A) AU Small Finance Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) Ujjivan Small Finance Bank / उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
- C) Jana Small Finance Bank / जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
- D) Equitas Small Finance Bank / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
- E) Slice Small Finance Bank / स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक

**Answer: Option E**

**Explanation | व्याख्या:**

- Slice Small Finance Bank (Slice SFB) has introduced three new financial products.
- स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक (Slice SFB) ने तीन नए वित्तीय उत्पाद पेश किए हैं।

- These include a Digital Savings Account linked to the RBI Repo rate, a UPI-integrated credit card, and digital Fixed Deposits (FDs).
- इनमें RBI रेपो रेट से जुड़ा डिजिटल बचत खाता, UPI-इंटीग्रेटेड क्रेडिट कार्ड और डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) शामिल हैं।
- Slice launched India's first savings account linked to 100% of the Repo rate of the Reserve Bank of India (RBI).
- स्लाइस ने भारत का पहला ऐसा बचत खाता लॉन्च किया है जो 100% RBI रेपो रेट से जुड़ा है।
- Interest on the savings account is calculated and credited daily, allowing real-time growth of money.
- इस बचत खाते पर ब्याज की गणना और जमा प्रतिदिन की जाती है, जिससे धन वास्तविक समय में बढ़ता है।
- The digital Fixed Deposits offer interest rates of up to 7.25% per annum.
- डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.25% प्रति वर्ष तक ब्याज दिया जाता है।
- These FDs are insured up to ₹5 lakh by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).
- ये एफडी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) द्वारा ₹5 लाख तक बीमित हैं।
- The card offers up to 3% cashback based on usage, a "Slice in 3" feature for no-cost Equated Monthly Investment (EMI) conversion on purchases above Rs.2,000, weekly rewards through Slice Sparks.

#### **About Slice Small Finance Bank :**

- Established : 2016
- HQ : Guwahati, Assam
- CEO Rajan Bajaj

**Ques: The Reinsurance Advisory Committee (RAC) has been reconstituted by which regulatory body?**

**रीइंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी (RAC) का पुनर्गठन किस नियामक संस्था द्वारा किया गया है?**

- A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- C) Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / भारतीय

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

D) Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) / पेंशन फंड  
नियामक एवं विकास प्राधिकरण

E) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

**Answer: Option C**

---

### Explanation | व्याख्या:

- The Reinsurance Advisory Committee (RAC) has been reconstituted by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
- रीइंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी (RAC) का पुनर्गठन भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा किया गया है।
- The committee has been reconstituted for a period of three years.
- समिति का पुनर्गठन तीन वर्षों की अवधि के लिए किया गया है।
- It has been constituted under Section 101B of the Insurance Act, 1938.
- इसका गठन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101B के अंतर्गत किया गया है।
- The RAC is chaired by A.V. Girija Kumar, former Chairman and Managing Director (CMD) of Oriental Insurance Company Limited (OICL).
- RAC के अध्यक्ष ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) ए.वी. गिरिजा कुमार हैं।
- Aruna Bowrampet, Deputy General Manager (Reinsurance), IRDAI, serves as the Secretary of the committee.
- IRDAI की डिप्टी जनरल मैनेजर (रीइंश्योरेंस) अरुणा बोवरामपेट समिति की सचिव हैं।
- The objective of the RAC is to strengthen IRDAI's advisory support on reinsurance-related matters.
- RAC का उद्देश्य रीइंश्योरेंस से जुड़े मामलों पर IRDAI की परामर्श सहायता को मजबूत करना है।

### About IRDAI :

- ESTD : 1999
- HQ : Hyderabad
- Chairman : Ajay Seth

**Ques: Which company recently received the Payment Aggregator–Physical (PA-P) licence from the Reserve Bank of India (RBI)?**

**हाल ही में किस कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर–फिजिकल (PA-P) लाइसेंस प्राप्त हुआ है?**

- A) Paytm Payments Services / पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज
- B) Razorpay / रेज़रपे
- C) Paysharp / पेसशार्प
- D) PhonePe / फोनपे
- E) BharatPe / भारतपे

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- Paysharp has received the Payment Aggregator–Physical (PA-P) licence from the Reserve Bank of India (RBI).
  - पेसशार्प को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर–फिजिकल (PA-P) लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
  - The licence enables Paysharp to operate as a physical (offline) payment aggregator.
  - यह लाइसेंस पेसशार्प को भौतिक (ऑफलाइन) पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।
  - This approval will help the company enhance its payment service offerings.
  - इस स्वीकृति से कंपनी अपनी भुगतान सेवाओं को और सुदृढ़ कर सकेगी।
  - Earlier, in August 2024, Paysharp had received the Payment Aggregator–Online (PA-O) licence.
  - इससे पहले, अगस्त 2024 में पेसशार्प को पेमेंट एग्रीगेटर–ऑनलाइन (PA-O) लाइसेंस प्राप्त हुआ था।
- 

**Ques: State Bank of India (SBI) has launched CHAKRA for what primary purpose?**

**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने CHAKRA किस मुख्य उद्देश्य के लिए लॉन्च किया है?**

- A) Promoting digital retail banking / डिजिटल रिटेल बैंकिंग को बढ़ावा देना
- B) Financing MSMEs only / केवल एमएसएमई को वित्तपोषण
- C) Financing sunrise sectors critical to India's economic transformation / भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों का वित्तपोषण
- D) Strengthening agricultural credit / कृषि ऋण को मजबूत करना
- E) Expanding overseas banking operations / विदेशी बैंकिंग परिचालन का विस्तार

**Answer: Option C**

---

### **Explanation | व्याख्या:**

- State Bank of India (SBI) has launched CHAKRA, a Centre of Excellence (CoE).
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने CHAKRA नामक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) लॉन्च किया है।
- CHAKRA aims to finance sunrise sectors that are critical to India's economic transformation.
- CHAKRA का उद्देश्य भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों को वित्तपोषित करना है।
- The combined potential investment in these sunrise sectors is estimated at around ₹100 trillion over the next five years.
- इन उभरते क्षेत्रों में अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹100 ट्रिलियन के संभावित निवेश का अनुमान है।
- SBI has estimated a lendable opportunity of about ₹20–22 trillion in these sectors during the same period.
- SBI ने इन क्षेत्रों में अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹20–22 ट्रिलियन के ऋण अवसर का अनुमान लगाया है।
- SBI has signed Memoranda of Understanding (MoUs) with 21 financial institutions.
- SBI ने 21 वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- Under these MoUs, project finance teams of partner institutions will work alongside the SBI team at CHAKRA.
- इन समझौतों के तहत साझेदार संस्थानों की परियोजना वित्त टीम CHAKRA में तैनात SBI टीम के साथ कार्य करेंगी।
- This collaboration will enable capacity building and co-financing of projects.
- इस सहयोग से क्षमता निर्माण और परियोजनाओं का सह-वित्तपोषण संभव होगा।

**Ques: In which month did UPI record its highest-ever transaction volume of about 21.6 billion?**

**UPI ने लगभग 21.6 अरब का अब तक का सबसे अधिक लेन-देन किस महीने में दर्ज किया?**

- A) October 2025 / अक्टूबर 2025
- B) November 2025 / नवंबर 2025
- C) August 2025 / अगस्त 2025
- D) September 2025 / सितंबर 2025
- E) December 2025 / दिसंबर 2025

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- UPI transaction volume reached a record 21.6 billion in December 2025, the highest ever recorded.
  - दिसंबर 2025 में UPI लेन-देन की संख्या 21.6 अरब तक पहुँच गई, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है।
  - This surpassed the previous record of 20.47 billion transactions in November 2025.
  - इसने नवंबर 2025 के 20.47 अरब लेन-देन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
  - The total value of UPI transactions in December 2025 rose to around ₹28 lakh crore.
  - दिसंबर 2025 में UPI लेन-देन का कुल मूल्य लगभग ₹28 लाख करोड़ रहा।
  - This value exceeded the earlier peak of about ₹27.3 lakh crore recorded in October 2025.
  - यह अक्टूबर 2025 में दर्ज ₹27.3 लाख करोड़ के पिछले उच्चतम स्तर से भी अधिक था।
  - The growth reflects increased digital payment adoption, festive spending, and expansion of the UPI ecosystem.
  - यह वृद्धि डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने, त्योहारी खर्च और UPI इकोसिस्टम के विस्तार को दर्शाती है।
-

**Ques: Who holds the record for presenting the highest number of Union Budgets in India?**

**भारत में सबसे अधिक केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है?**

- A) Manmohan Singh / मनमोहन सिंह
- B) Yashwant Sinha / यशवंत सिन्हा
- C) Nirmala Sitharaman / निर्मला सीतारमण
- D) Morarji Desai / मोरारजी देसाई
- E) P. Chidambaram / पी. चिदंबरम

**Answer: Option D**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- Finance Minister Nirmala Sitharaman is set to present her 9th consecutive Union Budget since assuming office in 2019.
  - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019 से अब तक लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं।
  - She has already presented eight consecutive Union Budgets, the longest continuous run by any Finance Minister in India.
  - उन्होंने अब तक लगातार 8 केंद्रीय बजट पेश किए हैं, जो किसी भी भारतीय वित्त मंत्री द्वारा सबसे लंबी निरंतर श्रृंखला है।
  - With the ninth Budget, she moves closer to the all-time record held by Morarji Desai.
  - 9वें बजट के साथ वह मोरारजी देसाई के सर्वकालिक रिकॉर्ड के और करीब पहुँच जाएंगी।
  - Former Prime Minister Morarji Desai holds the record for presenting the highest number of Union Budgets in India — a total of 10.
  - पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कुल 10 केंद्रीय बजट पेश किए थे, जो अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड है।
- 

**Ques: Under the revised Liberalised Remittance Scheme (LRS) rules, what is the new TCS rate on education and medical remittances above ₹10 lakh?**

**संशोधित लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) नियमों के तहत ₹10 लाख से अधिक शिक्षा और चिकित्सा रेमिटेंस पर नया TCS दर क्या है?**

- A) 1%
- B) 2%
- C) 5%
- D) 10%
- E) 20%

**Answer: Option B**

---

### **Explanation | व्याख्या:**

- Union Budget rationalised Tax Collected at Source (TCS) on outward remittances under RBI's Liberalised Remittance Scheme (LRS).
- केंद्रीय बजट ने RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी रेमिटेंस पर TCS को तर्कसंगत बनाया।
- TCS on education and medical remittances above ₹10 lakh has been reduced from 5% to 2%.
- ₹10 लाख से अधिक शिक्षा और चिकित्सा रेमिटेंस पर TCS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।
- The reduction will ease liquidity pressure and ensure more funds directly reach students and patients abroad.
- इस कमी से नकदी दबाव कम होगा और छात्रों व मरीजों तक अधिक धन सीधे पहुंचेगा।
- Lower TCS will reduce cash blockage at the point of remittance.
- कम TCS से रेमिटेंस के समय धन अटकने की समस्या घटेगी।
- TCS on overseas tour packages has also been rationalised to a flat 2%.
- विदेशी टूर पैकेज पर TCS को भी फ्लैट 2% कर दिया गया है।
- Earlier, overseas tour remittances attracted 5% TCS below ₹10 lakh and 20% above ₹10 lakh.
- पहले विदेशी टूर रेमिटेंस पर ₹10 लाख से कम पर 5% और ₹10 लाख से अधिक पर 20% TCS लगता था।
- In November 2025, total outward remittances under LRS stood at \$1,937 million, showing a decline from October.
- नवंबर 2025 में LRS के तहत कुल विदेशी रेमिटेंस \$1,937 मिलियन रहा, जो अक्टूबर की तुलना में कम है।

**Ques: Under Union Budget 2026–27, what is the revised Tax Collected at Source (TCS) rate on overseas tour packages?**

**केंद्रीय बजट 2026–27 के तहत विदेशी टूर पैकेज पर संशोधित स्रोत पर कर संग्रह (TCS) दर क्या है?**

- A) 5%
- B) 10%
- C) 20%
- D) 2%
- E) 1%

**Answer: Option D**

---

---

**Explanation | व्याख्या:**

- Under the Union Budget 2026–27, interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal (MACT) to a natural person has been exempted from income tax.
- केंद्रीय बजट 2026–27 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा प्राकृतिक व्यक्ति को दिया गया ब्याज आयकर से मुक्त कर दिया गया है।
- The TCS rate on overseas tour packages has been reduced from 5% 20% to 2% without any minimum amount threshold.
- विदेशी टूर पैकेज पर TCS दर को 5% 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है, बिना किसी राशि सीमा के।
- Under the Liberalised Remittance Scheme (LRS), the TCS rate for education and medical purposes has also been reduced from 5% to 2%.
- उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
- The time limit for revising income tax returns has been extended from 31 December to 31 March with a nominal fee.
- आयकर रिटर्न संशोधन की समय-सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, मामूली शुल्क के साथ।
- ITR-1 and ITR-2 filers can continue filing returns till 31 July, while non-audit business cases and trusts are allowed time till 31 August.
- ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले करदाता 31 जुलाई तक, जबकि नॉन-ऑडिट व्यवसाय मामलों और ट्रस्ट के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
- These measures aim to simplify compliance and enhance ease of living for

taxpayers.

- इन उपायों का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना और करदाताओं के लिए जीवन सुगमता बढ़ाना है।

---

**Ques: In which city did the State Bank of India launch a Global Trade Finance Centre (GTFC) to strengthen its trade finance and global banking operations? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्यापार वित्त और वैश्विक बैंकिंग संचालन को मजबूत करने के लिए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर (GTFC) किस शहर में शुरू किया?**

- A) Kolkata / कोलकाता
- B) New Delhi / नई दिल्ली
- C) Chennai / चेन्नई
- D) Mumbai / मुंबई
- E) Bengaluru / बेंगलुरु

**Answer: Option A**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- State Bank of India, India's largest Public Sector Bank, launched a Global Trade Finance Centre to strengthen its trade finance and global banking operations.
- भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्यापार वित्त और वैश्विक बैंकिंग संचालन को मजबूत करने के लिए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर शुरू किया।
- The GTFC was launched in Kolkata.
- यह GTFC कोलकाता में शुरू किया गया।
- In July 2025, SBI launched two specialized GTFCs in Kolkata and Hyderabad, Telangana, on the occasion of its 70th anniversary.
- जुलाई 2025 में, एसबीआई ने अपनी 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता और तेलंगाना के हैदराबाद में दो विशेष GTFC शुरू किए।
- The GTFC uses advanced technologies such as Artificial Intelligence, Machine Learning, and Blockchain.
- GTFC में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- The initiative marks a shift from traditional paper-based trade finance

systems to digital processes.

• यह पहल पारंपरिक कागज़-आधारित व्यापार वित्त प्रणालियों से डिजिटल प्रक्रियाओं की ओर बदलाव को दर्शाती है।

---

**Ques: What was the total value of UPI transactions in January, as per NPCI data?**

**NPCI के अनुसार जनवरी में UPI लेनदेन का कुल मूल्य कितना था?**

- A) ₹27.97 lakh crore
- B) ₹25.40 lakh crore
- C) ₹28.33 lakh crore
- D) ₹30.10 lakh crore
- E) ₹21.75 lakh crore

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- As per data released by the National Payments Corporation of India (NPCI), UPI transaction value touched a record high of ₹28.33 lakh crore in January.
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार जनवरी में UPI लेनदेन का मूल्य ₹28.33 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
- The total number of UPI transactions in January stood at 2,170 crore.
- जनवरी में कुल UPI लेनदेन 2,170 करोड़ दर्ज किए गए।
- In December, the UPI transaction value was ₹27.97 lakh crore, showing a sharp rise in January.
- दिसंबर में UPI लेनदेन का मूल्य ₹27.97 लाख करोड़ था, जो जनवरी में बढ़ गया।
- Month-on-month growth in UPI transaction value was recorded at 21%.
- मूल्य के आधार पर UPI लेनदेन में महीने-दर-महीने 21% की वृद्धि हुई।
- Average daily UPI transactions during January were around 70 crore.
- जनवरी में औसतन प्रतिदिन लगभग 70 करोड़ UPI लेनदेन हुए।
- The average daily transaction value stood at about ₹91,400 crore.
- औसत दैनिक लेनदेन मूल्य लगभग ₹91,400 करोड़ रहा।
- In January 2026, UPI transactions recorded a year-on-year growth of 28% in value terms.
- जनवरी 2026 में UPI लेनदेन मूल्य में 28% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

- NPCI noted that the growth momentum of UPI continues to strengthen with increasing adoption of digital payments.
  - NPCI के अनुसार डिजिटल भुगतान को अपनाने के साथ UPI की विकास गति लगातार मजबूत हो रही है।
- 

**Ques: What is the annual financing commitment under the new Country Partnership Framework (CPF) announced by the Government of India and the World Bank Group?**

**भारत सरकार और विश्व बैंक समूह द्वारा घोषित नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) के तहत वार्षिक वित्तपोषण प्रतिबद्धता कितनी है?**

- A) USD 3–5 billion
- B) USD 5–7 billion
- C) USD 6–8 billion
- D) USD 10–12 billion
- E) USD 8–10 billion

**Answer: Option E**

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Government of India and the World Bank Group announced a new Country Partnership Framework to accelerate job creation in both urban and rural areas.
- भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन को तेज करने के लिए नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क घोषित किया।
- The framework includes an annual financing commitment of USD 8–10 billion for the next five years.
- इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत अगले पाँच वर्षों के लिए USD 8–10 बिलियन का वार्षिक वित्तपोषण प्रस्तावित है।
- The new CPF came into effect from the beginning of January 2026.
- यह नया CPF जनवरी 2026 की शुरुआत से प्रभावी हुआ।
- The framework aligns with India's "Viksit Bharat" vision of becoming a developed nation by 2047.
- यह फ्रेमवर्क भारत के "विकसित भारत" विज़न के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है।

- The World Bank was established in 1944 and is headquartered in Washington D.C.
  - विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में स्थित है।
  - The World Bank has 189 member countries.
  - विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं।
- 
- 

**Ques: From which date will the Income Tax Act, 2025 come into effect?  
आयकर अधिनियम, 2025 किस तिथि से लागू होगा?**

- A) 1st January 2026
- B) 1st April 2025
- C) 1st April 2026
- D) 1st July 2026
- E) 31st March 2026

**Answer: Option C**

---

---

**Explanation | व्याख्या:**

- The Income Tax Act, 2025 will come into force from 1st April 2026.
- आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
- The Finance Minister announced that simplified Income Tax Rules and Forms will be notified soon.
- वित्त मंत्री ने बताया कि सरलीकृत आयकर नियम और फॉर्म जल्द अधिसूचित किए जाएंगे।
- Tax forms have been redesigned to make compliance easier for common taxpayers.
- आम करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने हेतु आयकर फॉर्म को पुनः डिज़ाइन किया गया है।
- The timeline for filing Income Tax Returns has been extended.
- आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई गई है।
- ITR-1 and ITR-2 filers can file returns till 31st July.
- ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले करदाता 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- Non-audit business cases and trusts will be allowed to file returns till 31st

August.

- नॉन-ऑडिट बिजनेस मामलों और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति होगी।
- The fiscal deficit for FY 2026–27 is estimated at 4.3% of GDP, lower than 4.4% in the current fiscal year.
- वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% अनुमानित है, जो वर्तमान वित्त वर्ष के 4.4% से कम है।
- No deduction will be allowed on interest expenditure related to dividend income or mutual fund income.
- डिविडेंड आय या म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज व्यय पर कोई कटौती अनुमन्य नहीं होगी।
- These provisions aim to improve ease of compliance and enhance ease of living for taxpayers.
- इन प्रावधानों का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना और करदाताओं के लिए जीवन सुगमता बढ़ाना है।

---

**Ques: Up to what level is the Government of India considering raising the FDI limit in Public Sector Banks (PSBs)?**

**सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में FDI सीमा कितनी करने पर विचार कर रही है?**

- A) 26%
- B) 40%
- C) 49%
- D) 51%
- E) 74%

**Answer: Option C**

---

**Explanation | व्याख्या :**

- The Union Government is considering raising the FDI limit in Public Sector Banks (PSBs) from 20% to 49%.
- केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में FDI सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है।

- The proposal aims to strengthen the capital base of state-run banks and make them more competitive with private sector banks.
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकारी बैंकों की पूंजी स्थिति को मजबूत करना और उन्हें निजी बैंकों के बराबर लाना है।
- Inter-ministerial consultations are currently underway regarding this proposal.
- इस प्रस्ताव को लेकर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श जारी है।
- The move was confirmed by Financial Services Secretary M. Nagaraju.
- इस कदम की पुष्टि वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने की है।
- At present, private banks are allowed up to 49% FDI, while PSBs remain capped at 20%.
- वर्तमान में निजी बैंकों में 49% तक FDI की अनुमति है, जबकि PSBs में सीमा 20% है।
- Higher FDI can help PSBs raise capital, expand lending capacity, and manage larger risks.
- अधिक FDI से PSBs को पूंजी जुटाने, ऋण विस्तार करने और बड़े जोखिम संभालने में मदद मिलेगी।
- The government believes India needs 3–4 globally large banks; currently, only SBI and HDFC Bank figure among the world's top lenders.
- सरकार का मानना है कि भारत को 3–4 वैश्विक स्तर के बड़े बैंक चाहिए, जबकि फिलहाल केवल SBI और HDFC Bank ही शीर्ष वैश्विक बैंकों में शामिल हैं।

**Ques : Which bank has signed a distribution agreement with HSBC Asset Management (India) Private Limited to offer its Mutual Fund products to customers?**

**किस बैंक ने अपने ग्राहकों को HSBC एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के म्यूचुअल फंड उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए वितरण समझौता किया है?**

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- D) Central Bank of India / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**Answer: Option D**

## Explanation | व्याख्या :

- Central Bank of India (CBI) has signed a distribution agreement with HSBC Asset Management (India) Private Limited.
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने HSBC एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ वितरण समझौता किया है।
- Under this partnership, CBI will offer HSBC AMC's Mutual Fund products to its customers.
- इस साझेदारी के तहत CBI अपने ग्राहकों को HSBC AMC के म्यूचुअल फंड उत्पाद उपलब्ध कराएगा।
- The offerings include equity, debt, and hybrid mutual fund schemes.
- इन पेशकशों में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड योजनाएँ शामिल हैं।
- These mutual fund products will be accessible through CBI's branches as well as its digital platforms.
- ये म्यूचुअल फंड उत्पाद CBI की शाखाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

## About Central Bank of India :

- Established : 1911
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Kalyan Kumar
- Tagline : Central to you since 1911

---

**Ques: Who has been approved by RBI as the Managing Director (MD) & CEO of YES Bank?**

**RBI ने YES बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और CEO के रूप में किसे मंजूरी दी है?**

- A) Prashant Kumar / प्रशांत कुमार
- B) Ravneet Gill / रवनीत गिल
- C) Vinay Muralidhar Tonse / विनय मुरलीधर टोंसे
- D) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E) Amitabh Chaudhry / अमिताभ चौधरी

**Answer: Option C**

---

## Explanation | व्याख्या :

- The Reserve Bank of India (RBI) has approved the appointment of Vinay Muralidhar Tonse as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of YES Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विनय मुरलीधर टोंसे को YES बैंक का प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
- The appointment has been approved for a term of three years.
- यह नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है।
- YES Bank is a private sector bank with its headquarters in Mumbai.
- YES बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
- As per banking regulations, RBI approval is mandatory for the appointment of MD & CEO of banks.
- बैंकिंग नियमों के तहत MD और CEO की नियुक्ति के लिए RBI की मंजूरी अनिवार्य होती है।
- The approval highlights RBI's supervisory role in ensuring fit and proper management of banks.
- यह मंजूरी बैंकों में उपयुक्त और सक्षम प्रबंधन सुनिश्चित करने में RBI की पर्यवेक्षी भूमिका को दर्शाती है।

---

**Ques : Which country's central bank approved the first USD-backed stablecoin named USDU?**

**किस देश के केंद्रीय बैंक ने USDU नामक पहले USD-समर्थित स्टेबलकॉइन को मंजूरी दी है?**

- A) United States / संयुक्त राज्य अमेरिका
- B) United Kingdom / यूनाइटेड किंगडम
- C) United Arab Emirates / संयुक्त अरब अमीरात
- D) Singapore / सिंगापुर
- E) Switzerland / स्विट्ज़रलैंड

**Answer: Option C**

---

## Explanation | व्याख्या :

- The Central Bank of the United Arab Emirates (UAE) has approved the country's first USD-backed stablecoin.
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के केंद्रीय बैंक ने देश के पहले USD-समर्थित स्टेबलकॉइन को मंजूरी दी है।
- The stablecoin is named USDU.
- इस स्टेबलकॉइन का नाम USDU है।
- USDU has been approved under the Payment Token Services Regulation framework of the UAE Central Bank.
- USDU को UAE केंद्रीय बैंक के पेमेंट टोकन सर्विसेज़ रेगुलेशन फ्रेमवर्क के तहत स्वीकृति दी गई है।
- The approval marks a significant step toward regulating digital assets and payment tokens in the UAE.
- यह मंजूरी UAE में डिजिटल एसेट्स और पेमेंट टोकन के विनियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- USDU is issued and managed by Universal Digital Intl Limited.
- USDU को यूनिवर्सल डिजिटल इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जारी और प्रबंधित किया जाता है।